

भारत सरकार  
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2513

दिनांक 13 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए

दहेज प्रतिषेध अधिनियम

2513. श्री टी. आर. बालू:

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या भारत में औसतन प्रतिदिन 20 महिलाएं दहेज उत्पीड़न के कारण अपनी जान गंवाती हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में विगत तीन वर्षों के दौरान केंद्र और राज्यों द्वारा क्या निवारक/दंडात्मक कार्रवाई की गई है;
- (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान दहेज हत्याओं और उत्पीड़न के लिए दंडित किए गए दोषियों का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या सरकार का दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 को और अधिक कठोर बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री  
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) महिलाओं के प्रति अपराध सहित अन्य अपराधों पर आंकड़ा संकलित करता है और अपने प्रकाशन "भारत में अपराध" (क्राइम इन इंडिया) में प्रकाशित करता है, जो कि एनसीआरबी की वेबसाइट <https://ncrb.gov.in> पर उपलब्ध है। उक्त रिपोर्ट वर्ष 202 तक की उपलब्ध है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2021-2023 के दौरान दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार दर्ज मामले, आरोप पत्र दाखिल मामले, दोषी ठहराए गए मामले, गिरफ्तार व्यक्ति, आरोप पत्र दायर व्यक्ति और दोषी ठहराए गए मामलों की विवरण की सूची **अनुलग्नक-I** में दी गई है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2021-2023 के दौरान दहेज के लिए हत्या (भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 304 ख) के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार दर्ज मामले, पीड़ितों की संख्या, आरोप पत्र दाखिल मामले, दोषी ठहराए गए मामले, गिरफ्तार व्यक्ति, आरोप पत्र दायर व्यक्ति और दोषी ठहराए गए व्यक्तियों की सूची **अनुलग्नक-II** में दी गई है।

“पुलिस” और “लोक व्यवस्था” भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने, नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा जिसमें दहेज के मामलों एवं दहेज के लिए हत्या की जांच एवं अभियोजन भी शामिल है, की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों की है और वे इससे निपटने में सक्षम हैं।

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 में दहेज की समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं। यह अधिनियम दहेज देने या लेने पर रोक लगाता है और इसके लिए दंड का प्रावधान करता है ताकि महिलाओं को दहेज उत्पीड़न से बचाया जा सके। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 दहेज उत्पीड़न को घरेलू हिंसा के दायरे में परिभाषित करता है और इसके तहत सुरक्षा आदेश, निवास आदेश, अभिरक्षा आदेश, आर्थिक सहायता, मुआवजा आदेश इत्यादि जैसे उपाय (रेमेडी) प्रदान करता है।

केंद्र सरकार महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और इस संबंध में विभिन्न विधायी और योजनाबद्ध कार्यक्रम लाए हैं। इनमें “भारतीय न्याय संहिता”, “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता”, “घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2006”, “दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961”, जैसे कानून शामिल हैं। इन कानूनी प्रावधानों के अलावा सरकार द्वारा अनेक योजनाएं और परियोजनाएं क्रियान्वित की गई हैं, जिनमें वन स्टॉप सेंटर (ओएससी); महिला हेल्पलाइनों का सार्वभौमिकरण (डब्ल्यूएचएल), आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) जो आपात स्थितियों के लिए अखिल भारतीय एकल नंबर (112)/मोबाइल ऐप आधारित प्रणाली है; जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से समुदाय में क्षमता निर्माण, पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्क (डब्ल्यूएचडी) की स्थापना/सुदृढीकरण इत्यादि शामिल हैं।

वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) योजना, जो पूर्णतः केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 से पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही है। यह निजी एवं सार्वजनिक दोनों जगहों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं और संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत सहायता और सहयोग प्रदान करता है। यह जरूरतमंद महिलाओं को चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और सलाह, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता, मनोवैज्ञानिक-सामाजिक परामर्श सहित कई तरह की सेवाएं भी प्रदान करता है। देश भर में 896 ओएससी कार्यशील हैं और दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 तक 12.88 लाख से अधिक महिलाओं की सहायता की गई है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुलिस स्टेशन महिलाओं के लिए अधिक अनुकूल और सुलभ हों, क्योंकि वे पुलिस स्टेशन में आने वाली किसी भी महिला के लिए संपर्क का पहला और एकमात्र बिंदु होते हैं, 14,658 महिला सहायता डेस्क (डब्ल्यूएचडी) स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 13,011 का नेतृत्व महिला पुलिस अधिकारी कर रही हैं। जरूरतमंद महिलाओं तथा संकटग्रस्त महिलाओं को सहायता एवं सहयोग प्रदान करने के लिए सभी 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस-112) स्थापित की गई है जिसमें क्षेत्र/पुलिस संसाधनों का कंप्यूटर की सहायता से प्रेषण शामिल है। ईआरएसएस के अलावा, पश्चिम बंगाल को छोड़कर 35 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में पूरी तरह से काम करने वाली विशिष्ट महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल -181) कार्यशील है। डब्ल्यूएचएल को भी ईआरएसएस के साथ भी एकीकृत किया गया है। महिला हेल्पलाइनों ने 31 दिसम्बर, 2025 तक 96.37 लाख से अधिक महिलाओं की सहायता की गई है।

पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) ने भी कई पहलें की हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, जांच अधिकारियों, अभियोजन अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम शामिल हैं। बीपीआरएंडडी ने "पुलिस स्टेशनों पर महिला सहायता डेस्क" के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी तैयार की है जिनका सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए चार महत्वपूर्ण घटकों अर्थात् बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षण, मानव संसाधन विकास और प्रतिक्रिया तंत्र पर ध्यान केंद्रित किया है। महिलाओं के प्रति अपराध की रोकथाम और जांच के लिए "महिला सुरक्षा और संरक्षा-पुलिस में प्रथम प्रतिक्रियाकर्ताओं और जांचकर्ताओं के लिए एक पुस्तिका" नामक एक पुस्तक भी तैयार की गई है जिसका उद्देश्य यौन हिंसा अपराध के विशिष्ट संदर्भ में जांच, पीड़ित को मुआवजा और पुनर्वास शामिल है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की रोकथाम और पता लगाने तथा अपराध के पीड़ितों के साथ समुचित बातचीत के लिए पुलिस बल में उचित व्यवहार और मनोवृत्ति कौशल विकसित करने पर जोर दिया गया है। बीपीआरएंडडी ने संवेदनशीलता के साथ महिला सुरक्षा, पुलिस कर्मियों का लैंगिक संवेदीकरण इत्यादि विषय पर वेबिनार भी आयोजित किए हैं।

मंत्रालय महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए समय-समय पर जागरूकता अभियान भी चलाता है। इसके अलावा, सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू), राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) और राज्यों में उनके जैसे संस्थानों के माध्यम से दहेज प्रथा की बुराइयों के प्रति जागरूकता फैलाने सहित महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और कानून के विभिन्न प्रावधानों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए सेमिनारों, कार्यशालाओं, ऑडियो-विजुअल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि के माध्यम से जागरूकता फैला रही है। इसके अतिरिक्त, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर परामर्श जारी किए हैं।

महिलाओं के लिए कानूनी सहायता को और अधिक सुलभ बनाने के लिए, राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) के सहयोग से कानूनी सहायता क्लिनिक शुरू किया है, जो मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करके महिलाओं की शिकायतों के समाधान के लिए एकल-खिड़की सुविधा है। 17 राज्यों में ऐसे ही कानूनी सहायता क्लिनिक स्थापित किए गए हैं। मंत्रालय ने दिनांक 22 जनवरी, 2025 को सभी कार्यात्मक सुविधाओं के साथ 'मिशन शक्ति पोर्टल' शुरू किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य महिलाओं के लिए विभिन्न सरकारी सेवाओं में पहुंच बढ़ाना, बचाव, सुरक्षा और पुनर्वास के लिए गुणवत्ता तंत्र स्थापित करना एवं विभिन्न योजनाओं और कानूनों के तहत पदाधिकारियों और कर्तव्य धारकों की क्षमता का निर्माण करना है।

इसके अलावा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डैक) द्वारा महिला हेल्पलाइन को कार्यान्वित करने वाले सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कॉल की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय डैशबोर्ड तैयार किया गया है। यह डैशबोर्ड प्राप्त कॉल और सहायता प्राप्त महिलाओं की तात्कालिक निगरानी करने की सुविधा प्रदान करता है। इस प्रणाली के माध्यम से, केंद्र सरकार भारत भर में महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली हिंसा पर केंद्रीकृत डेटा रख पाएगी, जिसे घरेलू हिंसा के मामलों सहित मामलों के प्रकार के अनुसार वर्गीकृत किया गया है।

\*\*\*\*\*

अनुलग्नक-1

‘दहेज प्रतिषेध अधिनियम’ विषय पर श्री टी. आर. बालू द्वारा पूछे गए दिनांक 13.02.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2513 के भाग (क) से (घ) में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष 2021-2023 के दौरान ‘दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961’ के अंतर्गत दर्ज मामले (सीआर), आरोप पत्र दाखिल मामले (सीसीएस), दोषी ठहराए गए मामले (सीओएन), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोप पत्र दायर व्यक्ति (पीसीएस) और दोषी ठहराए गए व्यक्ति (पीसीवी) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण।

2021							
क्रम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सीआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	आंध्र प्रदेश	11	246	0	456	2576	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3	असम	582	338	1	700	435	1
4	बिहार	3362	2364	44	2837	3831	60
5	छत्तीसगढ़	8	6	0	20	20	0
6	गोवा	0	0	0	0	0	0
7	गुजरात	3	3	0	8	8	0
8	हरियाणा	18	9	0	26	18	0
9	हिमाचल प्रदेश	0	1	0	1	1	0
10	झारखंड	1805	1293	82	1687	1735	91
11	कर्नाटक	1845	1806	29	4867	5264	52
12	केरल	39	21	0	46	31	0
13	मध्य प्रदेश	44	45	33	45	121	44
14	महाराष्ट्र	40	23	0	18	53	0
15	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
16	मेघालय	0	0	0	0	0	0
17	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
18	नागालैंड	0	0	0	0	0	0

19	ओडिशा	465	406	0	159	535	0
20	पंजाब	14	4	1	38	5	1
21	राजस्थान	4	0	1	0	0	2
22	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
23	तमिलनाडु	281	156	5	695	439	17
24	तेलंगाना	5	5	0	12	13	0
25	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	4594	3720	317	9529	15167	1267
27	उत्तराखंड	414	238	0	80	472	0
28	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0
	<b>कुल राज्य</b>	<b>13534</b>	<b>10684</b>	<b>513</b>	<b>21224</b>	<b>30724</b>	<b>1535</b>
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0
30	चंडीगढ़	1	0	0	1	0	0
31	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0
32	दिल्ली	16	13	0	34	27	0
33	जम्मू और कश्मीर	4	4	0	12	12	0
34	लद्दाख	0	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
36	पुदुच्चेरी	13	2	0	46	9	0
	<b>कुल संघ राज्य क्षेत्र</b>	<b>34</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>48</b>	<b>0</b>
	<b>कुल (अखिल भारत)</b>	<b>13568</b>	<b>10703</b>	<b>513</b>	<b>21317</b>	<b>30772</b>	<b>1535</b>

2022							
क्रम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सीआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	आंध्र प्रदेश	298	308	4	1239	1281	13
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3	असम	272	285	0	423	373	0
4	बिहार	3580	3711	43	4974	5281	58
5	छत्तीसगढ़	9	7	2	16	16	8
6	गोवा	0	0	0	0	0	0
7	गुजरात	1	1	0	1	1	0
8	हरियाणा	17	8	0	11	11	0
9	हिमाचल प्रदेश	1	0	0	0	0	0
10	झारखंड	1796	1498	126	2005	2017	153
11	कर्नाटक	2224	1734	7	5392	5484	11
12	केरल	28	39	0	65	61	0
13	मध्य प्रदेश	63	60	246	36	177	269
14	महाराष्ट्र	28	38	0	43	64	0
15	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
16	मेघालय	3	1	0	0	1	0
17	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
18	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
19	ओडिशा	34	31	4	1	51	4
20	पंजाब	4	3	0	7	5	0
21	राजस्थान	8	0	0	0	0	0
22	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
23	तमिलनाडु	220	197	2	836	658	5

24	तेलंगाना	6	5	0	0	8	0
25	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	4807	4565	1413	8060	16577	2651
27	उत्तराखंड	38	29	0	4	125	0
28	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0
	<b>कुल राज्य</b>	<b>13437</b>	<b>12520</b>	<b>1847</b>	<b>23113</b>	<b>32191</b>	<b>3172</b>
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0
30	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
31	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0
32	दिल्ली	18	8	0	43	23	0
33	जम्मू और कश्मीर	17	13	0	46	45	0
34	लद्दाख	0	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
36	पुदुच्चेरी	7	6	0	32	13	0
	<b>कुल संघ राज्य क्षेत्र</b>	<b>42</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>121</b>	<b>81</b>	<b>0</b>
	<b>कुल (अखिल भारत)</b>	<b>13479</b>	<b>12547</b>	<b>1847</b>	<b>23234</b>	<b>32272</b>	<b>3172</b>

2023							
क्रम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सीआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	आंध्र प्रदेश	353	194	0	58	675	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3	असम	162	154	0	207	178	0
4	बिहार	3665	3385	126	4362	5236	206
5	छत्तीसगढ़	8	7	1	21	21	2

6	गोवा	0	0	0	0	0	0
7	गुजरात	3	3	0	13	13	0
8	हरियाणा	14	5	0	8	8	0
9	हिमाचल प्रदेश	2	1	0	0	5	0
10	झारखंड	1487	1595	271	1965	2405	300
11	कर्नाटक	2322	2113	8	5697	5837	16
12	केरल	21	15	0	24	27	0
13	मध्य प्रदेश	65	60	3	15	191	3
14	महाराष्ट्र	17	17	0	10	41	0
15	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
16	मेघालय	2	2	0	1	6	0
17	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
18	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
19	ओडिशा	5	5	5	0	426	5
20	पंजाब	4	6	3	5	8	5
21	राजस्थान	1	1	0	3	3	0
22	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
23	तमिलनाडु	144	158	3	586	334	8
24	तेलंगाना	4	6	0	0	10	0
25	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	7151	6112	628	14054	26047	1110
27	उत्तराखंड	14	11	6	3	31	9
28	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0
	<b>कुल राज्य</b>	<b>15444</b>	<b>13850</b>	<b>1054</b>	<b>27032</b>	<b>41502</b>	<b>1664</b>
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0
30	चंडीगढ़	0	1	0	0	1	0

31	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0
32	दिल्ली	16	21	1	37	37	4
33	जम्मू और कश्मीर	15	13	0	35	34	0
34	लद्दाख	0	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
36	पुदुच्चेरी	14	8	0	50	31	0
	<b>कुल संघ राज्य क्षेत्र</b>	<b>45</b>	<b>43</b>	<b>1</b>	<b>122</b>	<b>103</b>	<b>4</b>
	<b>कुल (अखिल भारत)</b>	<b>15489</b>	<b>13893</b>	<b>1055</b>	<b>27154</b>	<b>41605</b>	<b>1668</b>

अनुलग्नक- II

'दहेज प्रतिषेध अधिनियम' के संबंध में श्री टी. आर. बालू द्वारा पूछे गए दिनांक 13.02.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2513 के भाग (क) से (घ) में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष 2021-2023 के दौरान दहेज के लिए हत्या (धारा 304 ख आईपीसी) के तहत दर्ज मामलों (सीआर), पीड़ितों की संख्या (वीआईसी), आरोप पत्र दाखिल मामलों (सीसीएस), दोषी ठहराए गए मामलों (कॉन), गिरफ्तार व्यक्तियों (पीएआर), आरोप पत्र दायर व्यक्तियों (पीसीएस) और दोषी ठहराए गए व्यक्तियों (पीसीवी) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

2021								
क्रम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सीआर	पीड़ित	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	आंध्र प्रदेश	108	109	159	9	354	416	20
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
3	असम	198	198	164	1	323	168	1
4	बिहार	1000	1000	931	128	1678	1420	149
5	छत्तीसगढ़	65	65	66	11	190	190	21
6	गोवा	0	0	0	0	0	0	0
7	गुजरात	11	11	10	1	31	31	2
8	हरियाणा	275	275	220	16	367	362	26
9	हिमाचल प्रदेश	2	2	1	0	2	2	0
10	झारखंड	281	281	229	47	326	321	52
11	कर्नाटक	158	163	175	14	411	411	36
12	केरल	9	9	9	0	22	11	0
13	मध्य प्रदेश	522	523	509	136	1516	1495	337
14	महाराष्ट्र	172	172	188	8	695	590	25
15	मणिपुर	2	2	0	0	1	0	0
16	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0
17	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0
18	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0

19	ओडिशा	293	293	352	5	599	646	5
20	पंजाब	69	69	53	11	182	127	24
21	राजस्थान	452	454	341	98	466	454	132
22	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0
23	तमिलनाडु	27	27	21	12	67	52	23
24	तेलंगाना	175	175	178	7	450	403	15
25	त्रिपुरा	22	22	32	3	71	62	3
26	उत्तर प्रदेश	2222	2235	1886	439	6073	5202	1063
27	उत्तराखंड	72	72	55	6	106	91	10
28	पश्चिम बंगाल	454	471	490	5	721	900	10
	<b>कुल राज्य</b>	<b>6589</b>	<b>6628</b>	<b>6069</b>	<b>957</b>	<b>14651</b>	<b>13354</b>	<b>1954</b>
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	1	1	0	1	5	0
30	चंडीगढ़	4	4	1	1	9	4	2
31	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	0	0	1	0	1	1	0
32	दिल्ली	141	144	122	6	279	230	13
33	जम्मू और कश्मीर	16	16	14	0	34	34	0
34	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
36	पुदुच्चेरी	2	2	1	0	4	2	0
	<b>कुल संघ राज्य क्षेत्र</b>	<b>164</b>	<b>167</b>	<b>140</b>	<b>7</b>	<b>328</b>	<b>276</b>	<b>15</b>
	<b>कुल (अखिल भारत)</b>	<b>6753</b>	<b>6795</b>	<b>6209</b>	<b>964</b>	<b>14979</b>	<b>13630</b>	<b>1969</b>

2022								
क्रम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सीआर	पीड़ित	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	आंध्र प्रदेश	100	101	107	8	352	292	15
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
3	असम	175	195	222	7	409	276	9
4	बिहार	1057	1057	1100	89	1787	2391	128
5	छत्तीसगढ़	57	63	56	27	163	156	70
6	गोवा	0	0	0	0	0	0	0
7	गुजरात	10	10	8	0	28	28	0
8	हरियाणा	234	234	173	20	265	238	32
9	हिमाचल प्रदेश	1	1	0	0	3	0	0
10	झारखंड	208	214	191	61	299	312	77
11	कर्नाटक	165	166	134	1	343	311	6
12	केरल	11	12	16	1	36	32	1
13	मध्य प्रदेश	518	520	513	185	1310	1314	403
14	महाराष्ट्र	180	184	171	7	652	459	11
15	मणिपुर	0	0	1	0	0	1	0
16	मेघालय	1	1	0	0	1	0	0
17	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0
18	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0
19	ओडिशा	263	263	276	19	280	576	23
20	पंजाब	71	71	61	4	146	143	10
21	राजस्थान	451	451	300	66	401	396	93
22	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0
23	तमिलनाडु	29	29	25	6	74	58	9

24	तेलंगाना	137	137	186	24	414	387	53
25	त्रिपुरा	25	25	28	1	50	61	1
26	उत्तर प्रदेश	2138	2142	1946	686	6076	5307	1608
27	उत्तराखंड	70	70	65	3	116	112	12
28	पश्चिम बंगाल	406	427	421	14	682	790	26
	<b>कुल राज्य</b>	<b>6307</b>	<b>6373</b>	<b>6000</b>	<b>1229</b>	<b>13887</b>	<b>13640</b>	<b>2587</b>
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0
30	चंडीगढ़	1	1	2	1	0	12	3
31	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव+	1	1	1	0	6	4	0
32	दिल्ली	131	131	144	1	300	245	1
33	जम्मू और कश्मीर	9	9	10	0	32	32	0
34	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
36	पुदुच्चेरी	1	1	4	0	7	7	0
	<b>कुल संघ राज्य क्षेत्र</b>	<b>143</b>	<b>143</b>	<b>161</b>	<b>2</b>	<b>345</b>	<b>300</b>	<b>4</b>
	<b>कुल (अखिल भारत)</b>	<b>6450</b>	<b>6516</b>	<b>6161</b>	<b>1231</b>	<b>14232</b>	<b>13940</b>	<b>2591</b>

2023								
क्रम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सीआर	पीड़ित	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	आंध्र प्रदेश	95	96	89	17	296	255	37
2	अरुणाचल प्रदेश	1	1	0	0	2	0	0
3	असम	101	107	130	7	223	186	7
4	बिहार	1143	1143	1198	73	2362	2297	107
5	छत्तीसगढ़	46	49	50	13	144	140	39

6	गोवा	1	1	0	0	0	0	0
7	गुजरात	12	12	12	0	35	35	0
8	हरियाणा	207	211	156	21	225	219	30
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	1	0	0	3	0
10	झारखंड	218	228	230	92	316	385	98
11	कर्नाटक	156	160	159	6	407	394	9
12	केरल	8	8	10	0	13	16	0
13	मध्य प्रदेश	468	469	437	193	1235	1244	450
14	महाराष्ट्र	170	173	159	7	508	414	21
15	मणिपुर	1	1	0	0	6	0	0
16	मेघालय	0	0	1	1	1	1	1
17	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0
18	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0
19	ओडिशा	231	231	218	18	229	533	26
20	पंजाब	44	44	48	6	127	95	14
21	राजस्थान	428	430	272	60	337	336	90
22	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0
23	तमिलनाडु	11	11	23	8	34	36	12
24	तेलंगाना	145	147	155	26	438	369	53
25	त्रिपुरा	21	21	28	5	55	55	8
26	उत्तर प्रदेश	2122	2141	1953	887	5500	5175	2086
27	उत्तराखंड	48	48	46	25	49	92	39
28	पश्चिम बंगाल	350	350	371	8	597	1006	24
	<b>कुल राज्य</b>	<b>6027</b>	<b>6082</b>	<b>5746</b>	<b>1473</b>	<b>13139</b>	<b>13286</b>	<b>3151</b>
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0
30	चंडीगढ़	4	4	3	0	6	4	0

31	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव+	0	0	2	1	8	8	1
32	दिल्ली	115	115	131	26	269	210	49
33	जम्मू और कश्मीर	9	9	6	1	10	10	1
34	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
36	पुदुच्चेरी	1	1	0	0	4	0	0
	<b>कुल संघ राज्य क्षेत्र</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>142</b>	<b>28</b>	<b>297</b>	<b>232</b>	<b>51</b>
	<b>कुल (अखिल भारत)</b>	<b>6156</b>	<b>6211</b>	<b>5888</b>	<b>1501</b>	<b>13436</b>	<b>13518</b>	<b>3202</b>

\*\*\*\*\*